S. No.	State/Union Territories	Groups Formed During 1992-93	Groups Formed During 1993-94	Groups Formed During 1994-95	Groups Formed During 1995-96	Groups Formed During 1996-97
3.	Assam	448	518	934	356	823
4.	Bihar	628	839	900	2697	2415
5.	Goa	30	40	26	36	36
6.	Gujarat	427	768	315	1092	1026
7.	Haryana	393	534	412	571	711
8.	Himachal Pradesh	265	270	362	265	129
9.	Jammu & Kashmir	155	246	1036	642	705
10.	Karnataka	581	590	696	755	2128
11.	Kerala	319	551	753	797	962
12.	Madhya Pradesh	629	901	1442	1592	1136
13.	Maharashtra	615	674	1254	2175	2522
14.	Manipur	440	451	104	259	265
15.	Meghalaya	86	84	206	182	360
16.	Mizoram	114	120	110	46	66
17.	Nagaland	170	200	300	106	53
18.	Orissa	208	330	736	1730	2094
19.	Punjab	336	545	502	625	482
20.	Rajasthan	251	625	175	962	600
21.	Sikkim	30	29	65	135	25
22.	Tamil Nadu	522	806	144	1363	1549
23.	Tripura	41	199	145	143	149
24.	Uttar Pradesh	1281	1441	1709	2252	3404
25.	West Bengal	346	290	371	838	1768
Union Territories						
1.	A & N Islands	40	24	15	26	59
2.	Daman & Diu	0	0	3	20	
3.	Lakashdweep	34	2	10	7	9
4.	Pondicherry	30	30	13		2
5.	D & N Haveli	80	80	55	16	14
		9029	15483	37964	37576	41345

Total Group Forward = 141397

बिहार के गांवों में पेयजल

101. **श्री एस० एस० अहलुवालिया:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में अनेक गांवों में सुरक्षित पेयजल की कोई व्यवस्था न होने के कारण वहां के लोग तालाबों और खड्डों का गंदा और कीटाणु युक्त पानी पीने को विवश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य के प्रत्येक गांव में पेयजल की आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु) : (क) इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उम्मीद है कि राज्य सरकार बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अन्तर्गत तथा उपमिशन सहित राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं को लागू करेंगे।

गांवों का शहरीकरण

102. **श्री रामजीलाल:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिणी दिल्ली और बाहरी दिल्ली में आज तक कितने गांवों का शहरीकरण किया गया है;

(ख) क्या महरौली जोन में स्थित गांवों अर्थात लाडो सराय, सैदुलाजाब, नेब सराय, मैदानगढ़ी इत्यादि का शहरीकरण हो गया है अथवा नहीं; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान कितने गांवों का शहरीकरण किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Diversion of Panchayati Raj Funds in West Bengal

103. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that huge funds have been diverted from Panchyati Raj Funds to other projects by West Bengal Government as reported in all newspapers of 6th July, 1997;

(b) whether it is also a fact that such diversion of funds to Bengal Government has deprived millions of people from getting financial help under Jawahar Rozgar Yojana; and

(c) what action Government have taken so far in the matter?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

गुजरात के जिलों में पेयजल हेतु सहायता

104. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार की ओर से राज्य में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य के पंचमहल, बनासकांठा और कच्छ जिलों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु की गई कार्रवाई का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान इन जिलों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को विश्व बैंक की सहायता उपलब्ध कराई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु): (क) गुजरात राज्य सरकार ने प्रभावित बसावटों में गुणवत्ता संबंधी समस्या को हल करने के लिए उप-मिशनों के तहत तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता के लिए बनासकांठा सहित सात जिलों के लिए परियोजनाएं भेजी हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत और न्यूनतम मूलभूत सेवाओं के अंतर्गत पेयजल योजनाएं चलाई जा रही हैं।

(ग) 1996-97 के दौरान गुजरात राज्य सरकार को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 41.97 करोड़ रुपये रिलीज किए गए थे। 1997-98 के दौरान अभी तक केन्द्रीय सहायता के रूप में 25.36 करोड़